युवाओं को गरीबी से बाहर निकालने में मददगार बनती दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

हुनर से जीतो जहां...

लातेहार के सुदूर ओबर गांव की सुशांति कुमारी आज पुणे के एक होटल में नौकरी कर अपन मां की भी मदद कर रही है. सिल्ली के कान्चो गांव की नमिता पिज्जा हट में काम कर खुद तो खड़ी हुई है. अपने घर-परिवार की मददगार साबित हो रही है. जमशेदपुर के ऐरो स्टोर में काम करनेवाले श्याम आज सीनियर एसोसिएट के पद पर कार्य कर रहे हैं, जहां इनकी तनख्वाह 15 हजार रुपये है. ये कुछ गांव की युवक-युवतियों की कामयाबी की मिसाल है. नये जमाने के साथ कदम मिलाते हुए अपने दम पर अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाती है. इनके आत्मविश्वास को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये दूर-दराज के गांवों से आये हैं. कुछ महीने पहले तक इन्होंने शहर देखा तक नहीं था, लेकिन तीन महीने की ट्रेनिंग ने सबकुछ बदल दिया. ये मुमकिन हुआ है डीडीयू-जीकेवाई यानी दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना की बदौलत. पढ़िए कुमार विकास की यह रिपोर्ट.

डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करतीं युवतियां.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल भारत के सपने को झारखंड में साकार करने के लिए रघुवर सरकार लगातार प्रयासरत हैं. ग्रामीण विकास विभाग के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के सपने को पंख देकर रोजगार की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.

गरीब युवाओं की आस है डीडीयू-जीकेवाई

रोजगार तलाश रहे झारखंड के लाखों गरीब युवाओं की सबसे बड़ी आस है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम का मकसद है बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के जरिये स्थायी रोजगार के लायक बनाना. इसके लिए तमाम जिलों में प्रशिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं, जहां जरूरतमंदों को हुनरमंद बनाया जा रहा है. डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्य के 24 जिलों में 114 प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं. दूर-दराज से आये युवाओं के लिए ये योजना गरीबी से बाहर निकलने की पहली और आखिरी उम्मीद है.

कौशल विकास प्रशिक्षण से युवाओं को जोड़ने की कोशिश

ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत है औपचारिक शिक्षा और बाजार की मांग के मुताबिक कौशल की कमी. डीडीयू-जीकेवाई के तहत दिये जानेवाले कौशल प्रशिक्षण में इन दिक्कतों को दूर करते हुए विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की कोशिश की गयी है.

चयन और प्रशिक्षण से प्लेसमेंट तक निःशुल्क

डीडीयू-जीकेवाई के तहत गरीब युवाओं को प्रशिक्षण ही नहीं, नौकरी मिलने और स्थायी आमदनी सुनिश्चित होने तक पूरा सपोर्ट भी दिया जाता है. योजना के तहत कम से कम 70 फीसदी प्रशिक्षुओं को कम से कम छह हजार रुपये की नौकरी दिलाने का लक्ष्य है. गांव में पले-बढ़े बच्चे जमाने की रफ्तार का मुकाबला कर सके, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है. इसके लिए प्रशिक्षुओं को सॉफ्ट स्किल यानी अंग्रेजी और कंप्यूटर के अलावा बोल-चाल के तौर-तरीके भी सिखाये जाते हैं. प्रशिक्षण से लेकर नौकरी और उसके बाद भी महीनों तक उनकी परफॉर्मेंस और मुश्किलों पर नजर रखी जाती है. गांव से निकले किसी गरीब युवा के लिए ये मदद बेशकीमती है. खास बात है कि उसे इसके लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. डीडीयू-जीकेवाई के तहत उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रशिक्षण और प्लेसमेंट तक सब कुछ निःशुल्क है. स्टडी मटेरियल और ड्रेस ही नहीं, प्रशिक्षुओं के लिए रहने और खाने का इंतजाम भी सरकार करती है. यही वजह है कि काफी संख्या में ग्रामीण युवा डीडीयू- जीकेवाई के साथ जुड़ रहे हैं. इसके जरिये उनके अधूरे सपने पूरे हो रहे हैं और नये सपने देखे जा रहे हैं. इनका बढ़ता आत्मविश्वास एक बड़े बदलाव की आहट है. इनके चेहरों की चमक बताती है कि हालात बदल रहे हैं. जिंदगी से हताश हो चुके लोग अब आनेवाले कल को बेहतर बनाने में जुटे हैं.

प्रशिक्षु युवाओं के सुख-सुविधा का विशेष ध्यान

प्रशिक्षण के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी एवं ट्रेड के चयन में विशेष ध्यान दिया जाता है. कौशल प्रशिक्षण के सिलेबस और ट्रेनिंग की क्वालिटी पर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की नजर रहती है, ताकि गुणवत्ता बरकरार रहें और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दिशानिर्देशों के तहत संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं के हर सुख- सुविधा का ख्याल भी रखा जाता है. ये सब मिलकर प्रशिक्षुओं को अच्छी जगह पर नौकरी दिलाने में मददगार साबित होते हैं.

ग्रामीण युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध

कौशल विकास से होनेवाला फायदा समाज के सभी तबकों तक पहुंचे, योजना में इसका प्रावधान भी किया गया है. इस योजना के तहत सिर्फ ग्रामीण इलाकों के युवाओं को ही आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. कुल बजट का 50 फीसदी अनुसूचित जाति-जनजाति और 15 फीसदी अल्पसंख्यों के लिए खर्च किया जाना है. प्रशिक्षुओं में से कम से कम एक- तिहाई महिलाओं का होना जरूरी है. जरूरतमंदों की पहचान और सुदूर गांवों के आखिरी युवा को भी इस कार्यक्रम में समेटा जा सके, इसके लिए अब सखी मंडलों की मदद भी ली जा रही है.

समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय एजेंडा

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के साढ़े पांच करोड़ संभावित कामगार हैं. विश्वभर में वर्ष 2020 तक 5.70 करोड़ कामगारों की कमी होने का अनुमान है. इससे देश के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिक लाभांश के रूप में बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने है. केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता का विकास के बल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दिया है.

बाजार आधारित ट्रेडस पर फोकस

आधुनिक बाजार में देश के ग्रामीण गरीबों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे- औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना. विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, वित्त पोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई इस अंतर को पाटने का काम करती है. झारखंड के विभिन्न जिलों में स्थापित किये गये केंद्रों में हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, नर्सिंग, टेलरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस रखा जाता है, जिनकी बाजार में मांग है.

शेष पेज 11 पर

पंचायतनामा | डायरी

उत्तर प्रदेश. पार्थ बंसल ने बनायी अदभुत छड़ी

कानपुर के पुखरायां नगर निवासी छात्र पार्थ बंसल ने इलेक्ट्रॉनिक छड़ी बनायी है. पार्थ को इसकी प्रेरणा अपनी दादी से मिली है. पार्थ की दादी पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं. दादी के प्रति पार्थ का अनूठा प्रेम पार्किंसंस के मरीजों के लिए यह आविष्कार मददगार बन गया है. पार्थ के इस अविष्कार के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया. आज उन्हें भविष्य के एक होनहार वैज्ञानिक के रूप में देखा जा रहा है. 13 वर्षीय पार्थ बंसल का जन्म पांच दिसंबर 2002 को हुआ था. बचपन से ही वह चुंबक, तार, सेल, बल्ब आदि चीजों से खेलने में ज्यादा वक्त गुजारता था. हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रखनेवाले पार्थ ने दादी के लिये कुछ ऐसे ही बनाने की सोचा.

झारखंड. रानी मिस्त्री बन आत्मनिर्भर बनीं रानी बेगम

पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर प्रखंड के तीनकोनिया गांव की रानी बेगम एक सफल रानी मिस्त्री बन गयी हैं. रानी बेगम अपने स्तर से करीब 20 शौचालयों का निर्माण कर चुकी हैं. शौचालय निर्माण के लिए रानी ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण भी लिया. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रानी बेगम राजमिस्त्री के तौर पर गांव में शौचालय निर्माण कार्य में जुट गयीं. इस कार्य में जेएसएलपीएस का भरपूर सहयोग मिला. साल 2016 में रानी बेगम सुहाना आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं. समूह से जुड़ने और गतिविधियों में सक्रिय रहने के क्रम में उन्होंने समूह से 12 हजार रुपये का लोन लेकर शौचालय बनाया, तो इस कार्य की हर ओर प्रशंसा होने लगी.